

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2-समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2009

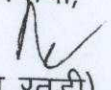
विषय:-छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन के एरियर की धनराशि का जी0पी0एफ0 में डाला जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-416/XXVII(1)/2009 दिनांक 18 जून, 2009 तथा शासनादेश संख्या-616/XXVII(1)/2009 दिनांक 24 सितम्बर, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (प्रतिलिपि संलग्न)

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि वेतन तथा पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर की 40% की धनराशि में से आयकर तथा नई पेंशन योजनान्तर्गत देय पेंशन अंशदान की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में वर्ष 2008-09 में जमा नहीं की गयी है तो उसे वर्ष 2009-2010 में देय एरियर की 30% धनराशि के साथ सम्मिलित करते हुए कुल 70% वेतन एवं पेंशन आदि की एरियर की धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कर ली जाए। नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को आयकर तथा अंशदान काटकर एरियर की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वेतन समिति के संस्तुतियों के कम में भविष्य निधि में डाली गयी धनराशि वर्ष 2010-2011 तक केवल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोड़कर आहरित न किया जाय।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या- 716 /XXVII/(1) 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 2-मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ। उत्तराखण्ड।
- 3-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6-निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 7-समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8-समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9-शासन के समस्त अनुभाग।
- 10-रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 11-स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 12-निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
- 13-निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव वित्त।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 24 सितम्बर, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन तथा पेंशन एवं ग्रैच्युटी के एरियर की धनराशि का भुगतान लेखानुदान के बजट से तथा वर्ष 2009-10 में भुगतान हेतु आदेशित 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान मूल बजट से किया जाना।

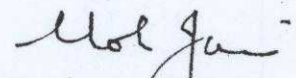
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-416/XXVII(1)/2009 दिनांक 18 जून, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं 3 में जिन सरकारी सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर के 40 प्रतिशत धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में वर्ष 2008-09 में जमा नहीं की गई है उनके एरियर के 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से करने हेतु एरियर की धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने एवं इसी प्रकार उन पेंशनर्स जिनके पेंशन एवं ग्रैच्युटी के अवशेष की 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान वर्ष 2008-09 में नहीं किया गया हो उन्हें उक्त 40 प्रतिशत अवशेष का भुगतान लेखानुदान अवधि हेतु प्राविधानित धनराशि से करने तथा वर्ष 2009-10 का बजट पारित हो जाने के पश्चात वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की 30 प्रतिशत धनराशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त मदों में पर्याप्त बजट व्यवस्था होने के बावजूद भी वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की उक्त कुल 70 प्रतिशत धनराशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।

अतः अनुरोध है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के सापेक्ष उपरोक्तानुसार कुल 70 प्रतिशत वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की धनराशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 616 (1)/XXVII(1)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. शासन के समस्त अनुभाग।
10. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
11. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,


(राधा रस्तूड़ी)
सचिव, वित्त

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 18 जून, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन तथा पेंशन एवं ग्रैज्युटी के एरियर की धनराशि का भुगतान लेखानुदान के बजट से तथा वर्ष 2009-10 में भुगतान हेतु आदेशित 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान मूल बजट से किया जाना।

नहोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-27/XXVII(7)(स्प0-1)/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 तथा शासनादेश संख्या-205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-7 में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के पश्चात वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने (जिसे 03 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा) एवं प्रस्तर-8 में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनर तथा दिनांक 01.01.2006 अथवा इसके बाद के सेवानिवृत्त पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैज्युटी आदि के अवशेष का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008-09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010-11 में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2009 के प्रस्तर-4 में वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो, तो उसका भुगतान माह जुलाई, 2009 के बाद ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जिन सरकारी सेवकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय एरियर के 40 प्रतिशत धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में

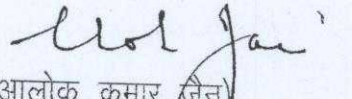
वर्ष 2008-09 में जमा नहीं की गई है उनके एरियर के 40 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से करने हेतु एरियर की धनराशि में से आयकर की धनराशि काटकर सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाय। इसी प्रकार उन पेंशनर्स, जिनके पेंशन एवं ग्रैच्युटी के अवशेष की 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान वर्ष 2008-09 में नहीं किया गया हो, उन्हें उक्त 40 प्रतिशत अवशेष का भुगतान लेखानुदान अवधि हेतु प्राविधानित धनराशि से कर दिया जाय।

3. वर्ष 2009-10 का बजट पारित हो जाने के पश्चात वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर की 30 प्रतिशत धनराशि को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4. वर्ष 2010-11 में वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर के अवशेष 30 प्रतिशत को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने/भुगतान करने की कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं 25 मार्च, 2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जायें और इसकी शेष सभी व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

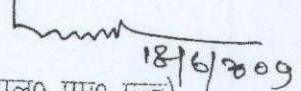

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 4/6 (1)/XXVII(1)/2009 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, सह स्टेट इन्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. शासन के समस्त अनुभाग।
9. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
10. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

आज्ञा से,


(एल0 एम0 पन्त)
सचिव, वित्त